

17

~~17~~



न्यायालय माननीय राजस्व अधिकारी तहसील ग्वालियर संभाग ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 14 सिविल R 474J/14

पुनरीक्षणकर्ता

1. विपइन सहकारी संस्था मर्यादित लटेरी जिला बिदिशा द्वारा प्रबंधक कमलेश शर्मा पुत्र श्री ज्वाला शर्मा उम्र लगभग 45 वर्ष निवासी तहसील लटेरी जिला बिदिशा म.प्र.

(Handwritten signature and text)
 17-2-14 को

बनाम

रसवा-डेन्ट्स

1. श्रीमान तहसीलदार, तहसील लटेरी जिला बिदिशा म.प्र.
2. राजस्व निरीक्षक मण्डल (1), आन्नदपुर तहसील लटेरी जिला बिदिशा म.प्र.

पुनरीक्षण याचिका राजस्व अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भूराजस्व संहिता 1959 जो कि विद्वान अधीनस्थ न्याययालय तहसीलदार लटेरी द्वारा मामला क्रमांक 2 / 2013-14 में पारित आदेश 31.01.2014 से उद्भूत हुई जिसके द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय को उक्त रूप से एवं विधि अनुसार ना की गई सीमांकन रिपोर्ट को स्वीकार किया गया उक्त आदेश की प्रति एनेक्जर ए-1 के रूप में संलग्न है।

पुनरीक्षण याचिका के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि विपइन सहकारी संस्था मर्यादित लटेरी जिला बिदिशा का म.प्र. सहकारी समिति का अधिनियम 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत है और उसका पंजीयन क्रमांक /ए आर/ बि.डी. एस/528 है उक्त संस्था की ओर से प्रबंधक उक्त पुनरीक्षण याचिका को प्रस्तुत करने के लिये सक्षम है। श्रीमान पत्र की प्रति एनेक्जर ए / 2 के रूप में संलग्न है।
2. यह कि उक्त संस्था को उक्त भूमि का पचासवां हिस्सा खसमे नम्बर 1152-53 में 100 * 100 फीट में बसाया जा चुका है। उक्त भूमि का पचासवां हिस्सा खसमे नम्बर 1152-53 में 100 * 100 फीट में बसाया जा चुका है। उक्त भूमि का पचासवां हिस्सा खसमे नम्बर 1152-53 में 100 * 100 फीट में बसाया जा चुका है।

(Handwritten notes and signatures on the left margin)

प्रकरण क्रमांक निग0 474-एक / 14

जिला -- विदिशा

स्थान तथा दिनांक	सर्ववाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-4-14	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। यह प्रकरण सरकारी मूमि पर अतिक्रमण किए जाने के संबंध में है जिसमें तहसीलदार ने आलोच्य आदेश द्वारा प्रकरण दर्ज कर आवेदक संस्था को जवाब हेतु सूचनापत्र जारी किए जाने के निर्देश दिए हैं। आवेदक को अपना पक्ष तहसीलदार के समक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है वे अपना पक्ष/evidence तहसीलदार के समक्ष रखें इस स्तर पर निगरानी ग्राह्य योग्य नहीं है। परिणामतः निगरानी अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>	<p>प्रशा. सदस्य</p>